नईदुनिया

फिलीपींस के पास उड़ता दिखा चीनी डब्लूजेउड-7 ड्रोन एक दिन पहले ही भारत से मिली है ब्रह्मोस मिसाइल

मनिला ।

चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक सोरिंग ड्रोन डब्लूजेउड-7 फिलीपींस के करीब उड़ता दिखाई दिया। गौरतलब है कि फिलपींस में हाल ही में भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन पश्चिम फिलीपीन सागर के पास उड़ता देखा गया था। चीन के साथ दूसरे थॉमस शोल और स्कारबोरो शोल सहित अन्य क्षेत्रीय विवादों के बीच चीनी ड्रोन दिखना चिंताजनक है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा उड़ाए गए डब्लूजेउड-7 जेट-संचालित ड्रोन की सर्विस सीलिंग 60,000 फीट से अधिक है। इसकी रेंज लगभग 4,350 मील है। 2022 में भी यही ड्रोन ताइवान स्ट्रेट के पास उड़ता दिखा था।

फिलीपींस, अमेरिका और जापानी का संयुक्त अभ्यास - मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपींस, अमेरिका और जापान की सेनाओं के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। यह अभ्यास सीधे अमेरिकी-फिलीपीन के द्विपक्षीय रक्षा रिश्तों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिलीपींस में अमेरिकी दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा, दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और तत्परता बढ़ाकर संधि। इस वर्ष, फिलीपींस और अमेरिकी सेना के 16 हजार से अधिक सदस्य एक साथ ट्रेनिंग लेंगे।

फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की डील के क्या मायने - चीन के पड़ोसी फिलीपींस की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा काफी अहम माना जा रहा है। फिलीपींस को यह मिसाइल प्रणाली ऐसे समय में मिली है, जब दक्षिण चीन सागर में लगातार होने वाली झड़पों के कारण उसका चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की तीन बैटरियों को फिलीपींस अपने तटीय क्षेत्रों में तैनात करेगा, ताकि क्षेत्र में किसी भी खतरे से बचाव किया जा सके। चीन और फिलीपींस के बीच जारी विवाद की जड़ में करीब आठ साल पुराना एक फैसला है। दरअसल, 2016 में हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा था कि फिलीपींस द्वारा दावा किया गया कि दक्षिण चीन सागर का एक विशेष हिस्सा अकेले फिलीपींस का है। हालांकि, चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया और विवादित जल क्षेत्र में अपने जहाज भेजना जारी रखा है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बना है। यह आपूर्ति दो साल पहले हुए एक समझौते के तहत की गई है। दरअसल, दोनों देशों के बीच 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ था। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) ने फिलीपींस को तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को लेकर 28 जनवरी, 2022 को फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

न्यूज ब्रीफ

पंजाब और पख्तूनख्वा की 21 सीटों पर उपचुनाव शुरू, कॉल और इंटरनेट सेवा पर पाबंदी, सेना की कड़ी निगरानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब और बलूचिस्तान के विशिष्ट जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को 21 प्रांतीय सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पाकिस्तान में आम चुनाव राष्ट्रीय असेंबली और चार प्रांतीय विधानसभा के लिए 8 फरवरी को हो चुका है। इस दौरान एक नेशनल असेंबली सीट, दो पंजाब विधानसभा सीट और खैबर खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा की एक सीट के लिए मतदान रद्द हो गया था। वहीं एक से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद केवल एक ही सीट चुनी। इस कारण से पाकिस्तान चुनाव आयोग को 21 सीटों पर उपचुनाव आयोजित करना पड़ा। इन 21 सीटों में पांच राष्ट्रीय और 16 प्रांतीय विधानसभा सीटें शामिल थीं। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 21 अप्रैल को उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। उपचुनाव से एक दिन पहले संघीय सरकार ने बताया कि उपचुनाव के दौरान पंजाब और बलूचिस्तान के विशिष्ट जिलों में सेलुलर सेवाएं और इंटरनेट बंद रहेगा। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। सीएएफ और पाकिस्तानी सेना भी रहेगी तैनात ईसीपी ने संघीय सरकार से शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और नागरिक सशस्त्र बल (सीएएफ) के सैनिकों की तैनाती को मंजूरी देने के लिए कहा था। आंतरिक मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपनी अधिसूचना में कहा कि सीएएफ और पाकिस्तान सेना इकाइयों को सुरक्षा के लिए सभी 21 निर्वाचन क्षेत्रों में 22 अप्रैल तक तैनात रहेंगे। इन्होंने छोड़ी थी सीटें पंजाब में कसूर और लाहौर सीटों को प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने खाली कर दिया। जबकि शहबाज ने लाहौर में अपनी दो प्रांतीय विधानसभा सीटें भी छोड़ दीं।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह जाएंगे चीन, अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा

वॉशिंगटन । अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जल्द ही चीन का दौरा करने वाले हैं। इसकी

जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ब्लिंकन 24 से 26 अप्रैल तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश विभाग का कहना है कि ब्लिंकन शंघाई और बीजिंग में चीनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। इस दौरान मध्य पूर्व संकट, यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध, क्रॉस-स्ट्रेट मुद्दे और दक्षिण चीन सागर पर भी बात होगी। इन मुद्दों पर भी होगी बात एक बयान में कहा गया, विदेश मंत्री नवंबर में वुडसाइड शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडन और शी द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चल रहे कार्यों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि काउंटरनार्कोटिक्स सहयोग, सैन्य-से-सैन्य संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर है। यह लोग भी रहेंगे मौजूद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ सार्वजनिक कूटनीति और सार्वजनिक मामलों की अवर सचिव लिज एलेन, पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डैनियल क्रिटेनब्रिंक, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स और कानून प्रवर्तन मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव टॉड रॉबिन्सन और साइबरस्पेस और डिजिटल नीति के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत नथानिएल फिक भी होंगे।

संसद के निचले सदन में यूक्रेन-इस्राइल के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी, बाइडन ने की थी अपील

वॉशिंगटन । राष्ट्रपति जो बाइडन की अपील के दो दिन बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में यूक्रेन के साथ-साथ पश्चिम एशियाई देश इस्राइल और युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता संबंधी पैकेज को मंजूरी मिल गई। सदन ने 61 अरब अमेरिकी डॉलर के यूक्रेन सहायता पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज को युद्धग्रस्त यूक्रेन को नए सिरे से अमेरिकी समर्थन की तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा सदन ने इस्राइल की सहायता करने और युद्धग्रस्त गाजा में लोगों को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी। प्रत्यक्ष सैन्य सहायता की घोषणा रिपोर्ट के अनुसार, सदन में यूक्रेन, इस्राइल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के लिए कुल 95.3 अरब डॉलर के पैकेज पर वोटिंग हुई। मंजूरी के बाद इसे सीनेट में भेज दिया गया। सहायता को मंजूरी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों का आभार प्रकट किया।

अमेरिका ने इस्राइल की एक सैन्य बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला

तेल अवीव ।

अमेरिका ने एक तरफ इस्राइल की मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो दूसरी तरफ आंखें टेढ़ी कर दी। अमेरिकी संसद ने इस्राइल के लिए 13 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस्राइल की एक सैन्य बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ये प्रतिबंध बटालियन द्वारा फलस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि, इस कदम की इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निंदा की है।

इस बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

फलस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राइली सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका वहां आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप में नेत्जाह येहुदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का एलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसी इस्राइली सैन्य टुकड़ी के खिलाफ बाइडन प्रशासन की पहली कार्रवाई होगी।

आगबबूला हुए पीएम नेतन्याहू

अमेरिका के इस संभावित कदम से इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खासे नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इस्राइली रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे सैनिक आतंकवादी से लड़ रहे हैं। आईडीएफ यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन है।

उन्होंने आगे कहा, मैं जिस इस्राइली सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, वह इन कदमों के खिलाफ सभी तरीकों से कार्रवाई करेगी। बता दें कि अमेरिका इससे पहले ईरान पर भी इस्राइल पर हमला करने के लिए कई तरह से प्रतिबंध लगा चुका है। इसके बाद इस्राइल के खिलाफ उनका एक्शन कई तरह के सवाल खड़े करते हैं।

हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना खतरे का संकेत

इस्राइली मंत्री इतामर बेन ग्विर और बेजेल स्मोट्रिच ने भी अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना की। ग्विर ने कहा, हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना खतरे का संकेत है। यह कदम बेहद गंभीर है और नेत्जाह येहुदा के सदस्यों की रक्षा की जानी चाहिए।

इस्राइली मंत्री इतामर बेन ग्विर और बेजेल स्मोट्रिच ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से भी अमेरिकी आदेश के आगे न झुकने का आह्वान किया। वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में नेत्जाह येहुदा पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।

इजरायल और ईरान की जंग बनेगी तीसरे विश्वयुद्ध का कारण : बाबा वेंगा

वॉशिंगटन। बुल्गारिया के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यिवाणियां सच हुई हैं। उन्होंने यूक्रेन में चेरनोबिल आपदा, राजकुमारी डायना की मृत्यु, न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक और यहां तक कि अपनी मौत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यिवाणी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई थी। 2024 के लिए उनकी भविष्यिवाणी में कहा गया है कि ईरान के साथ तनाव में ब्रिटेन और अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों के इजरायल के समर्थन में खड़े होने की संभावना है। ईरान रूस का समर्थन करता है और पुतिन यूक्रेन को खत्म करने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध की ओर हालात बढ़ सकते हैं। अगर रूस ने जंग शुरू की तो अमेरकिा और पश्चमिी देश चुप नहीं बैठेंगे। ईरान को सजा देने के लिए इजरायल को ताकत देंगे। उसे हथियार, गोला-बारूद मुहैया कराएंगे। क्योंकि उनका तो एक ही सपना है, हम पुतिन को यूक्रेन में जीतने नहीं दे सकते, हम ईरान को इजरायल को नष्ट करने नहीं दे सकते। हम जितना मजबूत होंगे, हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। सबसे ज्यादा डराने वाली भविष्यिवाणी उन्होंने 2024 के लिए की थी, जसिमें तृतीय विश्व युद्ध की चेतावनी दी गई थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2024 में आतंकी घटनाओं की लहर सी आएगी। एक प्रमुख देश जैवकि हथियारों का टेस्ट भी कर सकता है। इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। क्योंकि रूस में भयानक आतंकी हमला हुआ।

बुनियादी ढांचे के बढ़ते वजन से लाखों इमारतों पर खतरा जमीन में धंस रहे बड़े शहर

बीजिंग।

नए शोध में पता चला है कि चीन के करीब आधे प्रमुख शहरों पर पानी की निकासी और शहरी इमारतों व बुनियादी ढांचे के बढ़ते वजन के कारण खतरा मंडरा रहा है। जर्नल 'साइंस' में छपे इस शोध में पाया गया कि बीजिंग और तियानजिन समेत चीनी शहर भूस्खलन के 'मध्यम से गंभीर' जोखिम में हैं। शोध में चीनी जमीन के धंसने की दर भी बताई गई। अध्ययन के मुताबिक, चीन की 45 प्रतिशत शहरी भूमि प्रति वर्ष 3 मिलीमीटर से अधिक तेजी से धंस रही थी, जबकि 16 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 मिलीमीटर से अधिक की दर से धंस रही है।

अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने 2015 से 2022 की अवधि में 20 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले प्रत्येक चीनी शहर में भूमि धंसाव को मापा। उन्होंने जिन 82 शहरों की जांच की, उनमें से टीम ने पाया कि कुछ शहर तेजी से धंस रहे हैं। छह में से एक शहर प्रति वर्ष 10 मिमी से अधिक तेजी से धंस रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि शंघाई जहां लगातार डूब रहा है, वहीं बीजिंग वार्षिक रूप से 45 मिलीमीटर नीचे जा रहा है।

खनन व शहरी परिवहन नेटवर्क भी एक कारण

वैज्ञानिकों ने धंसते शहरों व भूजल क्षति के बीच एक मजबूत संबंध भी पाया, जो परत में खाली छिद्र छोड़ देता है और ऊपर वजन के ढेर में सिमट जाता है। शोध के अनुसार, अन्य कारकों में शहरी परिवहन नेटवर्क, साथ ही हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण और खनन शामिल हैं।

ढांचे की अखंडता के लिए बड़ा खतरा

शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा, चीन के शहरों की गिरावट को संबोधित करने की कुंजी भूजल निकासी के दीर्घकालिक, निरंतर नियंत्रण में निहित हो सकती है। ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में जलवायु अनुकूलन के प्रोफेसर रॉबर्ट निकोल्स ने कहा, यह धंसाव इमारतों और बुनियादी ढांचे की संरचनात्मक अखंडता के लिए बड़ा खतरा है और बाढ़ के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ाता है।

क्या डीपफेक के शिकार हो गए सिंगापुर के विदेश मंत्री चिट्ठी में मिली फर्जी तस्वीरें और वसूली की धमकी

सिंगापुर ।

सिंगापुर में भारतीय मूल के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन को धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें उनकी कुछ

तस्वीरें भी हैं, जिनसे छेड़खानी की गई है। इस धमकी भरे खत में वसूली की बात भी लिखी गई है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकृष्णन ने कहा है कि उन्हें और कई अन्य सांसदों को ऐसे पत्र मिले हैं, जिनमें धमकी के साथ फर्जी तस्वीरें भेजी गई हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि विदेश मंत्री और अन्य सांसदों को डाक पत्रों के माध्यम से तस्वीरें भेजी गई हैं। तस्वीरों में कुछ चेहरे दिख रहे हैं, जो कथित तौर पर अंतरंग स्थिति को दर्शा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मार्च से लेकर अब तक ऐसी 70 से अधिक रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं। पत्रों में कुछ ई-मेल एड्रेस दिए गए हैं और लिखा गया है कि अगर ई-मेल पर संपर्क नहीं किया गया, तो इसके परिणाम बुरे होंगे। पुलिस का कहना है कि जब पीड़ितों द्वारा ई-मेल पर संपर्क किया जाता है, तो उनसे बैंक अकाउंमट में रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। साथ ही यह धमकी भी दी जाती है कि अगर रुपये ट्रांसफर नहीं किए तो तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाएगा।

विदेश मंत्री ने जताई डीपफेक की आशंका सिंगापुर के विदेश मंत्री बालकृष्णन का कहना है कि आजकल डीपफेक के मामले चल रहे हैं और सभी को मिलकर इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद उन्हें भी वसूली की धमकी दी गई। विदेश मंत्री के अनुसार आसान टूल्स के साथ कोई भी कुछ ही मिनटों में डीपफेक सामग्री बना सकता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखना है कि आगे क्या होता है।

प्रशिक्षण के दौरान हादसे का शिकार हुए दो सैन्य हेलीकॉप्टर, क्रैश में एक की मौत, सात लापता

टोक्यो।

जापानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिसमें अब तक एक का शव बरामद हुआ है, अन्य सात लोग लापता हैं। हालांकि अब तक दोनों हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण पता नहीं लग पाया है। वहीं लापता सात लोगों की खोज जारी है। जापान के दो हेलीकॉप्टर रात में प्रशांत महासागर के इजू द्वीप पर पनडुब्बियों का मुकाबला करने का अभ्यास कर रहे थे। टोरीशिमा द्वीप के पास रात 10: 38 के आसपास एक हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया, उसके कुछ क्षणों बाद ही विमान से एक आपातकालीन सिग्नल प्राप्त हुआ। इसके लगभग 25 मिनट बाद करीबन 11: 04 पर इसी क्षेत्र में प्रशिक्षण कर रहे दूसरे विमान से भी संपर्क टूट गया। जापान के आत्मरक्षा बल (एसडीएफ) के एक प्रवक्ता ने एएफपी घटना की पुष्टि की और कहा कि एक व्यक्ति को बचाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। रक्षामंत्री माइनोरू किहारा का कहना है कि समुद्र में विमान का हिस्से देखे गए हैं। जिससे अंदाजा लगाया जा

रहा है कि दोनों दुर्घटनाग्रस्त हुए। हालांकि अब तक दुर्घटना का सही कारण नहीं पता चल पाया है, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। एक चालक दल के सदस्य को बचाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। लापता अन्य सात लोगों की खोज जारी है। मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स ने कहा कि आस-पास के जल क्षेत्र में कोई अन्य विमान या जहाज नहीं था, इसलिए घटना में किसी अन्य देश की संलिप्ता की संभावना नहीं है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे

पिछले साल अप्रैल में एक सेना के हेलीकॉप्टर का दक्षिणी ओकिनावा में मियाको द्वीप पर एक्सीडेंट हो चुका है। इसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें दो पायलट, दो मैकेनिक और एक सेना जनरल और अन्य सवार थे। इनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। वहीं जनवरी 2022 में भी एक लड़ाकू जैट मध्य इशिकावा में पानी में क्रैश हुआ था। इसमें बैठे दो पायलट की मौत हो गई थी। यही नहीं 2019 में एक स्टील्थ जेट का प्रशिक्षण मिशन पर उत्तरपूर्वी जापान से उड़ान भरने के बाद समुद्र में क्रैश हुआ। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी सेना का एक ऑस्प्रे सैन्य विमान जापान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई थी।

जापान रक्षा पर बढ़ा रहा है खर्चा

जापान इन दिनों देश की सुरक्षा के पर खास ध्यान दे रहा है। लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया के कई देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है। सूत्रों की मानें तो इन दिनों चीन की आक्रामता और उत्तर कोरिया के कारण जापान अपनी सुरक्षा व्यव्यस्था पर खर्च बढ़ा चुका है।

लंदन मेयर पद की दौड़ में शामिल हुआ दिल्ली में जन्मा यह शख्स, पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को देंगे चुनौती

लंदन।

इंग्लैंड के लंदन में मेयर पद पर पाकिस्तान मूल के सादिक खान तीसरी बार जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, इस बार उन्हें भारतीय मूल के एक उम्मीदवार से चुनौती मिलने वाली है। इनका नाम है तरुण गुलाटी। दिल्ली में जन्मे तरुण का कहना है कि लंदन के नागरिकों को सभी राजनीतिक पार्टियों ने दुखी किया है। उन्होंने आगे कहा कि वह लंदन को अनुभवी सीईओ की तरह चलाना चाहते हैं, जिससे सभी को लाभ मिल सके। उनका मानना है कि एक व्यवसायी और निवेश विशेषज्ञ के रूप में उनका अनुभव लंदन को लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तरुण गुलाटी

दो मई को होने वाले मेयर चुनाव में 63 वर्षीय भारतीय मूल के तरुण गुलाटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरेंगे। मेयर पद के लिए उनकी लड़ाई 13 अन्य उम्मीदवारों से होने वाली है। उन्होंने सिटीबैंक और एचएसबीसी के साथ छह देशों में काम किया है। एचएसबीसी में वह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक (आईएम) थे। तरुण गुलाटी ने कहा, मैं लंदन को एक अनोखे वैश्विक शहर के तौर पर देखता हूं। यह विश्व के वैश्विक बैंक की तरह है, जहां दुनियाभर के लोग एकत्रित होते हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा, मेयर के तौर पर मैं लंदन की बैलेंस शीट इस तरह से तैयार करूंगा कि यह निवेश के लिए एक प्रमुख विकल्प बन सके। इसमें सभी निवासियों के लिए सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो।

मैं एक अनुभवी सीईओ की तरह लंदन को प्रभावी ढंग से बदलूंगा। यहां लाभप्रदत्ता का मतलब सभी के लिए लाभ होगा। इस यात्रा में आप सभी शामिल होंगे। इसे अपने लंदन और अपने घर के लिए करें। लंदन की सड़कों में सुरक्षा उनके मुख्य एजेंडा में प्रमुख है।

इन नीतियों को खत्म करना चाहते हैं तरुण गुलाटी

लेबर पार्टी के मौजूदा नेता सदिक खान की कुछ अलोकप्रिय नीतियों को खत्म करना भी तरुण गुलाटी का प्रमुख एजेंडा है। सादिक खान की इन नीतियों में अल्ट्रा लो एमिशन जोन (यूएलईजेड) शुल्क और लो ट्रैफिक नेबरहुड (एलटीएन) से जुड़ी उच्च लागत को खत्म करना शामिल है।

तरुण गुलाटी ने कहा, हम यूएलईजेड, एलटीएन जैसी खराब नीतियां नहीं चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमें इसके प्रभावों को कम करने की जरूरत है। हमें जो भी परिवर्तन करना होगा, वह जनता की राय के अनुरूप होना चाहिए।

टैक्स जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित

तरुण गुलाटी ने मेयर पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार सुजैन हॉल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक लंदन असेंबली के सदस्य होने के बावजूद वह इन नीतियों को रोकने में नाकाम रही हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर राजनीतिक उम्मीदवार वह करते जो उन्हें करना चाहिए था, तो मैं मेयर पद की दौड़ में कभी शामिल नहीं होता।

तरुण गुलाटी किफायती आवासीय व्यवस्था, लंदन में पर्यटन को बढ़ावा देना, मुफ्त स्कूल भोजन सुनिश्चित करना और काउंसिल टैक्स को कम करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।